

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
30.07.2015 को राज्य सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 1123

यूरेनियम की अत्यधिक कमी

1123. श्री किरनमय नन्दा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सरकार देश में यूरेनियम के निक्षेप में अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए कौन-कौन से कदमों पर विचार कर रही है;
- (ख) क्या देश में यूरेनियम के नए निक्षेपों की खोज करने के लिए पुरजोर प्रयास किए जाने का उपयुक्त समय है; और
- (ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

- (क) असैन्य नाभिकीय सहकार पर हस्ताक्षर हो जाने के परिणामस्वरूप, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीईई), सुरक्षोपायों के अधीन वाले नाभिकीय रिएक्टरों जोकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के लिए खुले हैं, की ईंधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरेनियम अयस्क का आयात करता रहा है। तदनुसार, निम्नलिखित संगठनों/देशों के साथ संविदागत करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

- (1) मैसर्स अरेवा, फ्रांस
- (2) मैसर्स जेएससी टीवीईएल कारपोरेशन, रूस
- (3) मैसर्स एनएसी कजाटॉमप्रॉम, कजाखिस्तान
- (4) मैसर्स नावोई माइनिंग एंड मेटालार्जिकल कॉम्बिनेट कंपनी (एनएमएमसी), उजबेकिस्तान
- (5) मैसर्स कैमिको, कनाडा

(ख) आठ रिएक्टरों नामतः, कैगा, कर्नाटक स्थित कैगा विद्युत उत्पादन केन्द्र (केजीएस) 1 से 4 तक; कलपाक्कम, तमिलनाडु स्थित मद्रास परमाणु बिजलीघर (एमएपीएस) 1 तथा 2; तारापुर,

(ग) महाराष्ट्र स्थित तारापुर परमाणु बिजलीघर (टीएपीएस) 3 तथा 4; के लिए ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति स्वदेशी संसाधनों से की जाती है। जून, 2015 की स्थिति के अनुसार, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग (डीईई) के अधीन एक संघटक यूनिट है, ने, यूरेनियम का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण का कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप 2,25,936 टन स्व-स्थाने U_3O_8 (1,91,594 टन यूरेनियम) के भंडारों का पता चला है। अन्वेषण संबंधी कार्यकलाप, निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएँ हैं, जिन्हें देश भर में विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाता है। सरकार ने, नई खानें तथा संसाधन सुविधाएँ खोलकर स्वदेशी ईंधन की आपूर्ति को बढ़ाने के प्रयास किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की क्षमता के उपयोग में उत्तरोत्तर सुधार परिलक्षित हुआ है।